रणजीत टाइम्स

इंदौर

सोमवार , 21 जुलाई , 2025

वर्ष 01 | अंक 182 | कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

मतदान केंद्रों पर सुनेंगे प्रधानमंत्री जी की "मन की बात" समग्र भारत का प्रतीक है- मन की बात_सुमित मिश्रा

20 जुलाई शाम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, आगामी रविवार 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम मन की बात को भाजपा कार्यकर्ता मतदान केंद्र स्तर पर सुनेंगे, शहर के प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रमुख भाजपा नेता उपस्थित रहेंगे। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है, देश की विविध भाषा, भौगोलिक स्थिति, और विकास की सकारात्मक रोड मैप का परिचायक है। मतदान केंद्र स्तर पर प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंट को जन-जन तक पहुंचाएंगे। बैठक में नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी टीनू जैन, मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, कैलाश शर्मा, रघुवीर पटेल, श्रीमती अंजू मखीजा, सुधीर कोले , सविता अखंड आदि उपस्थित थे।

ट्रेफिक मित्र अभियान के तहत इंदौर में महिलाओं के लिए नि:शुल्क लर्निंग लाइसेंस शिविर पर उमड़ी महिलाओं की भीड़

बड़ी संख्या में महिलाएं एवं छात्राएं पहुँच रही लर्निंग लाइसेंस बनवाने

इंदौर । नारी शक्ति को सशक्त बनाने और उन्हें ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देशन में इंदौर नगर निगम, परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में, आज से इंदौर के सभी नगर निगम झोन कार्यालय ट्रेफिक मित्र अभियान के अंतर्गत "ट्रैफिक शक्ति" निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा जिसमे आरटीओ और ट्रेफिक मित्र की टीम के साथ नगर निगम की टीम भी मौजूद है ।महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया से परिचित कराना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और ट्रैफिक व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।इंदौर की सभी महिलाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएं।

सिहासा पंचायत क्षेत्र में ईकेवाईसी को लेकर लगातार जागरूकता अभियान जारी

इन्दौर धार रोड ग्राम पंचायत सिहासा द्वारा ईकेवाईसी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है अभियान में पंचायत के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर थम लगाकर केवाईसी की जा रही है वही अभी कुछ दिन पहले समग्र आईडी में शासन के राशन को लेकर केवाईसी करवाई गई थी ग्रामीण जन उसी केवाईसी को ईकेवाईसी समझ रहे थे और दोबारा ईकेवाईसी करवाने पर ध्यान नहीं दे रहे थे लेकिन रहवासियों का ध्यान ईकेवाईसी करवाने की तरफ आकर्षित करने के लिए सचिन पहलाद नील ने अनाउंसमेंट के साथ-साथ ढोल द्वारा डुंडी पिटवाई ईकेवाईसी जागरूकता अभियान चलाया जिसमें पंचायत के कर्मचारियों द्वारा अनाउंसमेंट कर बताया कि शासन की योजनाओ लाभ लेना है तो समस्त ग्रामवासियों को ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य हैअधिकतर लोगों के आधार कार्ड अपडेट नहीं होने के कारण ईकेवाईसी करवाने में समस्या आ रही है सिहासा क्षेत्र की आम जनता ने पंचायत क्षेत्र में सरकार से आधार कैंप लगवाने की मांग की है इस मौके पर सरपंच नारायण चौहान.मुकेश यादव जनपद सदस्य.महेश चौहान समाजसेवी.दुर्गा जोशी कंप्यूटर मास्टर.रामनिवास चौहान सहायक रोजगार.गजराजसिंह शक्तावत. रणजीतसिंह शक्तावात.दिनेश आर्य. अजय चौहान सहित ग्रामीणजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे ध्यान रहे जनता को सुविधा एवं शासन की योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत सिहासा क्षेत्र में देर रात तक ईकेवाईसी अभियान चलाया जा रहा है।

सरपंच सोहराब पटेल ने मंच लगा कर किया कावड़ यात्रा का स्वागत

इंदौर। इंदौर के बाग ग्रामीण क्षेत्र के मरीमाता मंदिर से महाकालेश्वर मंदिर तक निकलने वाली कावड़ यात्रा का बाघ सरपंच सोहराब पटेल द्वारा मंच लगाकर स्वागत किया यह कावड़ यात्रा जागृति मित्र मंडल द्वारा कई वर्षों से निकाली जा रही है।

बेहतर मंच संचालन का आधार, शब्द, ध्वनि और विचार

भोपाल। उद्घोषणा की गुणवत्ता का पैमाना सिर्फ़ अच्छी आवाज़ के साथ ही भाषा, ज्ञान, विचार, स्मृति और संस्कार भी होते हैं। मंच की कसौटियों को पार करते हुए सारा आत्म विश्वास और कौशल इसी बुनियाद पर टिका होता हो। जाने- माने उद्घोषक और कला समीक्षक विनय उपाध्याय ने यह विचार मैनिट केंपस में युवाओं के बीच साझा किए। क्रिएटिव यूथ फोरम 'तूर्यनाद' द्वारा यह आयोजन 'द पोडियम टीम' के सहयोग से किया गया। मंच उद्घोषणा कला कौशल पर केंद्रित थी जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में विनय उपाध्याय प्रतिभागियों से रुबरु हुए। इस आयोजन का उद्देश्य हिंदी में वाचिक परंपरा के साथ नई विचार यात्रा शुरू करना है। विनय उपाध्याय ने लगभग दो घंटे के सतत संभाषण में युवा प्रतिभागियों को बोलने की कला के तकनीकी और व्यावहारिक पक्षों का मार्गदर्शन किया। प्रश्नोत्तर के साथ संवाद को गति देते हुए उन्होंने बताया कि मीडिया क्रांति के इस दौर में सार्थक भाषा और ध्वनि को लेकर अनेक चुनौतियां हैं जो सिर्फ एक गंभीर उद्घोषक ही अनुभव करता है। विनय उपाध्याय ने अपने उदबोधन की शुरुआत में संस्कृत, हिंदी और कुछ लोक पदों का उदाहरण देते हुए जीवन और अस्तित्व में नाद और ध्वनि की बुनियादी उपस्थिति और महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। विनय ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित अनेक विभूतियों के समारोहों के मंच संचालन के अपने रोचक अनुभव सुनाए। विनय उपाध्याय ने बताया कि एक उद्घोषक के लिए जरूरी है कि उसका शब्दज्ञान,स्मृति और सामयिक संदर्भों की जानकारी मजबूत हो।

उन्होंने बताया कि उद्घोषक की भाषा और ज्ञान पर अपने परिवेश और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बहुत प्रभाव होता है। इस सब के बावजूद किसी भी उद्घोषक के लिए लगातार पढ़ना और वाचिक अभ्यास करना अनिवार्य है। 'तूर्यनाद' हिंदी समिति के संयोजक आशुतोष ठाकुर ने बताया कि इस संवाद श्रृंखला में आने वाले समय में मंच संचालन तथा उदघोषणा कला पर विस्तृत कार्यशाला आयोजित की जाएगी। सत्र का संचालन गोपाल कृष्ण पाठक ने किया।

भोपाल में समाजवादी पार्टी ने लगाई सांकेतिक विधानसभा

प्रदेश अध्यक्ष बोले- एमपी में 52 प्रतिशत ओबीसी, आबादी के बराबर आरक्षण दिया जाए

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठाते रहे हैं। रविवार को भोपाल में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सपा पदाधिकारियों ने सांकेतिक विधानसभा लगाकर मप्र सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मप्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ और मप्र में ओबीसी वर्ग को 52 प्रतिशत आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर एक अगस्त को भोपाल में विधानसभा घेराव करने की बात कही।

सपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- मप्र में ओबीसी को 52 प्रतिशत आरक्षण मिले: सांकेतिक विधानसभा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे। उन्होंने सांकेतिक सदन में ये मुद्दा उठाया। मनोज यादव ने कहा कि कई राज्यों में ओबीसी वर्ग को 42त्न तक आरक्षण है। लेकिन, मप्र की

भाजपा सरकार 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं कर रही है। मप्र में ओबीसी वर्ग की आबादी 52 प्रतिशत है, इसलिए मप्र में अन्य पिछड़े वर्गों को 52 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए।

सभापति के रोल में थे यूपी के पूर्व मंत्री: सपा कार्यालय में लगाई गई सांकेतिक विधानसभा के सभापति की भूमिका में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व श्रम मंत्री कुंवर बादशाह सिंह थे। बादशाह सिंह मायावती सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नेता सदन की भूमिका सपा के राष्ट्रीय सचिव सतेन्द्र यादव ने निभाई।

जमकर हुई नारेबाजी

सांकेतिक विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर वादाखिलाफी और जनविरोधी नीतियां लागू करने के आरोप लगाए तो सत्ता पक्ष ने इसका जवाब दिया। पक्ष-विपक्ष के बीच सदन में नारेबाजी हुई और विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सभापति ने बिल पारित कराकर सदन को स्थगित कर दिया।

घायल छात्रा से मिलीं राज्यमंत्री श्रीमती गौर

लापरवाही पर जताई नाराजगी, निरीक्षण कर बोलीं- समय पर अवगत कराते तो टल सकता था हादसा

- **अधिकारियों को हर संभव मदद करने के दिए निर्देश**

भोपाल (नप्र)। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बरखेड़ा स्थित पीएमश्री महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल का औचक निरीक्षण किया। हाल ही में स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से घायल हुई छात्रा संजना गिरी से वे उनके घर जाकर मिलीं और स्वास्थ्य की जानकारी ली। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने निरीक्षण के दौरान स्कूल प्रबंधन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर समय रहते हमें छत की जर्जर हालत की जानकारी दी जाती, तो यह हादसा टल सकता था। सरकार के पास

बजट की कमी नहीं है, लेकिन समस्या से अवगत कराना आवश्यक है। यह दुर्घटना स्पष्ट रूप से प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है। घटना में घायल हुई 10वीं की छात्रा संजना गिरी ने बताया कि हादसे में सिर पर चोट लगने से टांके आए हैं। राज्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्ची का सिटी स्कैन कराया जाए और इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। साथ ही डॉक्टर को निर्देशित किया जाए कि बारिश के मौसम में टांकों की नियमित जांच की जाए। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने यह भी कहा कि छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाएं। यदि बच्ची को चलने में परेशानी हो रही है, तो तीन पहिया वाहन की व्यवस्था के लिए कलेक्टर को आवेदन दिलवाया जाए और आवश्यक आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई जाए। इस मौके पर श्री सुरेंद्र घोटे, पार्षद श्री नीरज सिंह, श्री बी. शक्तिराव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मां का इलाज कराने आए युवक का एक्सीडेंट, मौत

अस्पताल के बाहर सड़क पार करते समय लोडिंग वाहन ने कुचला, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

भोपाल (नप्र)। भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर अस्पताल के बाहर सड़क पार कर रहे युवक को अज्ञात लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। घटना शनिवार की है, इलाज के दौरान रविवार की सुबह साढ़े नौ बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक ब्यावरा का रहने वाला था। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अशोक नायक (45) पिता रामचंद्र नायक शहीद कॉलोनी ब्यावरा में रहते थे। उनकी मां को पिछले दिनों पैरालिसिस अटैक आया था। मां का इलाज कराने अशोक भोपाल आए थे। मां को शुक्रवार की सुबह भोपाल मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया था। उनकी देखरेख करने अशोक अस्पताल में ही ठहरे हुए थे। अशोक अपने एक दोस्त से मिलने पहुंचे थे, जो भोपाल के एयरपोर्ट रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती है।

शासकीय भवनों की छतों पर बिना निवेश के लगेंगे सोलर रूफटॉप संयंत्र

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना'' में रेस्को पद्धति से लगेंगे सोलर सिस्टम

- **प्रदेश के सभी शासकीय भवन दिसम्बर-2025 तक किये जाने हैं सौर ऊर्जीकृत**
- **सभी जिलों के लिये पृथक-पृथक निविदाएँ जारी कर माँगी गयी दरें**

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2030 तक 500 गीगा वॉट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मध्यप्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित कर रहे है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना'' में प्रदेश के सभी शासकीय भवनों को दिसम्बर-2025 तक सौर ऊर्जीकृत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये आईएससीओ द्वारा सभी जिलों में पृथक-पृथक निविदाएँ जारी कर दर आमंत्रित की गयी है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने बताया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना'' में प्रदेश में राज्य शासन के भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति अंतर्गत सोलर रूफ़टॉप संयंत्र लगाने हैं। शासकीय विभागों को इन सौर परियोजनाओं में कोई निवेश नहीं करना होगा।

शासकीय कार्यालयों द्वारा ऊर्जा के उपयोग के लिए आरईएससीओ विकासक को प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। रेस्को द्वारा लगाये गये संयंत्र की प्रति यूनिट दर विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दर (जिसमें शासकीय कार्यालय भी शामिल हैं) से काफी कम होगी। इस प्रकार शासकीय कार्यालय शून्य निवेश, पहले दिन से बचत, नेट जीरो'' के सिद्धांत पर कार्य कर सकेंगे। आरईएससीओ परियोजना अंतर्गत म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा प्रत्येक जिले के लिए पृथक-पृथक निविदा जारी की गई है। इसमें आरईएससीओ विकासकों से प्रत्येक जिले के लिए पृथक-पृथक दर माँगी गई है। प्रत्येक जिले की न्यूनतम दर के आधार उस जिले में आरईएससीओ परियोजनाएँ स्थापित होंगी। भोपाल जिले में अधिकतम 15.6 एमडब्ल्यू की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जबकि ग्वालियर जिले में 5.26 एमडब्ल्यू, इंदौर जिले में 3.12 एमडब्ल्यू, छिंदवाड़ा जिले में 1.43 एमडब्ल्यू, दतिया जिले में 1.4 एमडब्ल्यू, धार जिले में 1.34 एमडब्ल्यू की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। शासकीय विभागों/संस्थाओं के भवन पर आरईएससीओ इकाई द्वारा 25 वर्ष की अवधि के लिये सोलर रूफ़टॉप संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। इस पूरी अवधि तक सोलर रूफ़टॉप संयंत्र का रख-रखाव आरईएससीओ इकाई द्वारा किया जाएगा। आरईएससीओ की आय पूरी तरह से 25 वर्ष तक सौर ऊर्जा के उत्पादन पर आधारित है। इससे आरईएससीओ विकासक सौर संयंत्र से अधिकतम उत्पादन की कोशिश करेंगे, जिससे शासकीय विभागों को अधिकाधिक लाभ होगा। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2018 से 2020 के बीच म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा राज्य में 133 शासकीय कार्यालयों में सफलतापूर्वक आरईएससीओ पद्धति से सोलर रूफ़टॉप संयंत्र लगाए, जो सफलतापूर्वक संचालित हैं। इसमें आईआईएम इंदौर सीएपीटी भोपाल, शासकीय मेडिकल कॉलेज (रीवा, शिवपुरी, खण्डवा, दतिया, विदिशा), एनएलआईयू भोपाल, एजी कार्यालय ग्वालियर, एसएआई भोपाल, भारत सरकार का पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन आदि शामिल हैं। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सफल एवं दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन से निश्चित ही प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में होगा।

रणजीत टाइम्स

कांग्रेस विधायकों के लिए 'नव संकल्प शिविर' का आयोजन

वरिष्ठ नेताओं और विशेषज्ञों के साथ बनेगी मिशन 2028 की रणनीति

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। श्री सिंघार ने बताया कि धार जिले के मांडू में 21 और 22 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की ओर से ÷नव संकल्प शिविर÷ का आयोजन किया जा रहा है। इस दो दिवसीय शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजनीतिक विशेषज्ञ और प्रेरक वक्ता विधायकों के साथ गहन चिंतन कर अपने अनुभव साझा करेंगे।

श्री सिंघार पिछले 2 दिनों से मांडव में रुककर लगातार तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिविर को वर्चुअली श्री राहुल गांधी जी भी संबोधित करेंगे, जो विधायकों को पार्टी की रणनीति, मूल्यों और समकालीन राजनीतिक चुनौतियों पर मार्गदर्शन देंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि इस शिविर में कुल 12 सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी के इतिहास, आजादी के आंदोलन में उसके योगदान, संगठनात्मक रणनीति और पार्टी की भविष्य की योजना पर चर्चा होगी।

नेता प्रतिपक्ष श्री सिंघार ने कहा कि कांग्रेस की नई सोच-नई रणनीति, मिशन 2028 और राज्य की जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विधायकों से मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ भाजपा सरकार को घेरने और जनता की जनसमस्याओं पर मंथन कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

शिविर को संबोधित करने वाले प्रमुख नेता एवं वक्ता:

- जीतू पटवारी – अध्यक्ष, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी
- हरीश चौधरी – प्रदेश प्रभारी
- सोनू शर्मा – प्रेरक वक्ता
- भगवंदेव इसरानी – पूर्व प्रमुख सचिव, म.प्र. विधानसभा
- कमलनाथ – पूर्व मुख्यमंत्री
- विवेक तन्खा – सांसद, राज्यसभा
- पवन खेड़ा – अध्यक्ष, एआईसीसी मीडिया विभाग
- अजय माकन – कोषाध्यक्ष एवं सांसद, राज्यसभा
- सुश्री सुप्रिया श्रीनेत – अध्यक्ष, कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है क्योंकि सभी विधायक नेता हैं। ये मिशन 2028 की तैयारी के तहत नव संकल्प शिविर है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से ना सिर्फ पार्टी संगठन मजबूत होगा बल्कि और ज्यादा मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक हम जनता के मुद्दे उठाएंगे।

पुष्य नक्षत्र में सवार होगी वर्षा

मेष वाहन पर आएंगे मेघ, राजनीतिक उथल-पुथल

महंगाई और संक्रमण रोगों की भी आशंका

भोपाल (नप्र)। 20 जुलाई से वर्षा का प्रवेश पुष्य नक्षत्र में हो गया। भारतीय ज्योतिषशास्त्र में वर्षा के आठ नक्षत्रों में पुष्य को तीसरा और अत्यंत प्रभावशाली नक्षत्र माना गया है। ज्योतिष मठ संस्थान के पं. विनोद गौतम के अनुसार, 20 जुलाई से 3 अगस्त तक वर्षा पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में होगी। इस नक्षत्र की वर्षा मेष वाहन, जला नाड़ी व चंद्र-चंद्र योग के कारण अच्छी मानी जा रही है। इसके चलते आगामी दिनों में अच्छी और संतुलित वर्षा के संकेत हैं।

पं. गौतम ने बताया कि मेघमाला ग्रंथ में वर्णित पुष्य नक्षत्र की स्थिति के अनुसार, जब इसमें केवल सूर्य गतिमान रहता है, तब वर्षा की संभावना प्रबल हो जाती है। हालांकि ग्रहों की स्थिति यह भी इंगित कर रही है कि सूर्य-बुध का योग कर्क राशि में तथा मंगल-केतु का योग सिंह राशि में होने से कुछ समय के लिए वर्षा में बाधा भी आ सकती है।

कर्क संक्रांति के प्रभाव भी दिखेंगे

पं. गौतम के अनुसार, वर्तमान समय में कर्क संक्रांति का असर भी मौसम और राजनीति पर स्पष्ट दिखाई देगा। पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा से नुकसान की संभावना है। वहीं सिंह राशि में मंगल-केतु की युति राजनीतिक अस्थिरता और विवादों की स्थिति निर्मित कर सकती है। यह स्थिति कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी। मेघमाला ग्रंथ में वर्णित पुष्य नक्षत्र की स्थिति के अनुसार, जब इसमें केवल सूर्य गतिमान रहता है, तब वर्षा की संभावना प्रबल हो जाती है।

महंगाई और रोग बढ़ने के संकेत

शेयर बाजार में तेज उतार-चढ़ाव के साथ ही सोना-चांदी और अन्य कीमती धातुओं में कीमतें बढ़ सकती हैं। मंगल-केतु के प्रभाव से देश में संक्रमण रोगों में भी वृद्धि की आशंका जताई गई है। हालांकि पं. गौतम यह भी कहते हैं कि बुद्धिजीवियों और शिक्षा जगत के लिए यह समय शुभ संकेत दे रहा है। अगस्त में जब सूर्य और बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो सकारात्मक और ऊर्जावान प्रभाव देगा।

पेट्रोल पंप के टैंक में भंडारित डीजल में पानी मिला, पंप सील किया गया

जांच के दौरान डीजल के स्टॉक में 451 लीटर का अंतर मिला

इंदौर। जिले में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक एवं सही माप से डीजल-पेट्रोल सहित अन्य ईंधन उपलब्ध कराए जाने के लिए अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपर कलेक्टर गौरव बेनल के मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टैंक में भंडारित डीजल में पानी पाये जाने पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया। इस पंप द्वारा नोजल से उपभोक्ताओं को मानक मात्रा से कम

डीजल प्रदाय किया जाता था। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा बार-बार दिये गये निर्देशों के बावजूद भी पंप पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये पीयूसी सेंटर भी स्थापित नहीं किया था। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि राऊ स्थित पेट्रोल पंप 'यूनाइटेड ऑटो सर्विस' की जांच पम्प के प्रबंधक प्रिंस पिता प्रीतपाल टुटेजा की उपस्थिति में खाद्य विभाग के अमले द्वारा की गई। जांच के दौरान डीजल के स्टॉक में 451 लीटर का अंतर होना पाया गया। ऑयल कंपनी द्वारा छूट मानक स्तर की सीमा से अधिक पाया गया। डीजल के नोजल से 5 लीटर की माप में मात्रा का परीक्षण करने पर 5 लीटर मानक ईंधन प्रदाय करना नहीं पाया गया एवं लगभग 20 एमएल तक कम प्रदाय किया जाना पाया गया। डीजल के भूमिगत टैंक में संग्रहित डीजल में वाटर टेस्टिंग पेस्ट द्वारा परीक्षण करने पर 2 सेंटीमीटर कुल 22 लीटर पानी मिला होना पाया गया। मौके पर पम्प परिसर में पीयूसी सेंटर का संचालन होना नहीं पाया गया। मौके पर उपभोक्ताओं को पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स होने संबंधी जानकारी का प्रदर्शन होना नहीं पाया गया। मौके पर फर्स्ट एड बॉक्स में पर्याप्त दवाइयां होना नहीं पायी गई। उपरोक्त अनियमितताएं कारित करने से यूनाइटेड ऑटो सर्विस (आईओसी कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पम्प) राऊ के प्रबंधक से भूमिगत टैंक में उपलब्ध 890 लीटर डीजल (एचएसडी) जिसकी बाजार कीमत कुल 81 हजार 909 रुपये आंकी गई है तथा उपभोक्ताओं के हित में पेट्रोल पंप को न्यायालय के आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है।

डिप्रेशन तथा तनाव, जैसी मानसिक व्याधियों में अत्यंत कारगर है सहजयोग

इस घोर कलियुग में मानसिक समस्या एक बहुत बडी त्रासदी है। मानसिक रोग यानि सिर्फ पागलपन नहीं पर डिप्रेशन भी है। अपने मन को स्वयं के काबू में नहीं रख पाने से ही ऐसी समस्याएं आती है। इस प्रतियोगिता वाले युग में स्वंय को औरों से कम पाने पर इंसान अंदर ही अंदर घुटने लगता है और मानसिक व्यथा को झेलता है।

सफल इंसान भी और ज्यादा पाने की ललक में स्वयं को इस प्रतियोगिता से दूर नहीं रख पाता है और मन की समस्या का सामना करने को विवश होता है। हम सभी ने अपने जीवन में कई गलतियां की होती है, जिसे हम भले ही सबसे छुपा लें पर अपने आप से नहीं छुपा सकते हैं। हमारी इन गलतियों को ईश्वर सदैव क्षमा कर देते हैं पर हम और हमारा अंतर्मन स्वयं को निर्दोष मानने से रोक नहीं पाते हैं और कितना भी चाहे इस आंतरिक अपराध बोध से मुक्ति नहीं मिलती। मानसिक व्याधियों का एक बड़ा कारण अपराध बोध का भार ही है। असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति और बड़ा अपराध कर बैठता है अथवा आत्महत्या जैसा पाप कर बैठता है, जैसे कि अंत में हिटलर ने किया था। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक ब्रायन बांस ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि पुनर्जन्म सत्य है और जीव अपने पूर्वजन्मों के कर्मों के अनुरूप अगले जन्म में वैसी मनोस्थिति व व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। अक्सर लोग मनोचिकित्सकों या आध्यात्मिक गुरुओं के पास अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए जाते हैं, परंतु आज तक इस व्याधि का कोई कारगर इलाज संभव नहीं हुआ है। विशेषज्ञों के मतानुसार पश्चाताप और विवेक ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा इससे कुछ हद तक मुक्ति पाई जा सकती है। पश्चाताप यदि केवल दिखावे के लिए किया जाएगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। साधारणतया लोग यह सोचते हैं कि इसके लिए बस एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है जो सर्वप्रथम अपराधी के विवेक को जाग्रत करता है और उसके बाद उसे पश्चाताप की सही विधि बताता है। इसीलिए आदिकाल में राक्षसों के भी गुरु होते थे जैसे कि शुक्राचार्य थे। परंतु सहज योग ध्यान प्रक्रिया में मानव को स्वयं का गुरु बनाकर मानसिक व्यथा से मुक्त किया जाता है। श्री माताजी कहती हैं निर्दोष भाव से मुक्त हो अपने अंतर के ईश्वर से एकाकारिता ही आत्मोन्नति का मार्ग है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर। उर्ध्वगामी होती है और विशुद्धि चक्र को स्पर्श करती है तब हमारे अन्दर का दोषी भाव पूर्णरुपेण समाप्त होता है और हम स्वयं पूर्णतया निर्दोष हो जाते है। यह भाव हमारे प्रगति मार्ग को प्रशस्त करता है।

सहजयोग की प्रणेता परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए 1जुलाई1992 को दिए गए प्रवचन में कहा था, "मैं चाहती हूं कि आपके मन में अपने प्रति बहुत मधुर भावना रहे। आपने जो भी गलतियाँ की हैं, उन्हें भूल जाइए। इसे भूल जाओ क्योंकि यह सर्वव्यापी शक्ति क्षमा का सागर है, इसलिए आप ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते जो करुणा के इस सागर में पूरी तरह से विलीन न हो सके।" श्री माताजी का यह कथन तभी संभव हो पायेगा जब सहज योग पद्धति से ध्यान कर भूतकाल के दुष्प्रभाव से छुटकारा पायें। चलिये हम सभी इस करुणा के सागर में विलीन हो स्वयं को अंदर से शक्तिशाली बनाते हैं, जुड़ते हैं सहज योग से।

क्या बिहार में सुशासन अब जंगलराज में बदल रहा है?

आरजेडी-कांग्रेस भाजपा और नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि जिनके शासन में कभी सुशासन की मिसाल दी जाती थी, अब वही शासन अपराधियों के आगे बेबस नजर आ रहा है। बिहार के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। सरकार को चाहिए कि वह पुलिस-प्रशासन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दे, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे और राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करे। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ किया जाए ताकि अपराधियों को जल्द सजा मिले। बिहार इस समय एक निर्णायक मोड़ पर है। अन्यथा एक ओर पुराना भयावह जंगलराज लौटने की आशंका है, दूसरी ओर एक सक्षम, उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन की आवश्यकता। यदि वर्तमान सरकार इस संदेश को नहीं समझती, तो आगामी विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिख सकते हैं, जिसमें सुशासन नहीं, जनाक्रोश निर्णायक भूमिका निभाएगा।

ललित गर्ग

बिहार में एक बार फिर कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बेखौफ अपराधियों का आतंक, दिन-दहाड़े हत्याएं, लूट, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध यह संकेत दे रहे हैं कि 'सुशासन बाबू' के नाम से मशहूर नीतीश कुमार का प्रशासन कहीं अपने वादों और आदर्शों से भटकता नजर आ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव की दस्तक के बीच आमजन में यह सवाल तेजी से उभर रहा है कि क्या बिहार में सुशासन अब फिर से जंगलराज में तब्दील हो रहा है? क्योंकि व्यापारियों, राजनेताओं, वकीलों, शिक्षकों और आम नागरिकों को निशाना बनाकर की गई लगातार हत्याओं ने बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। पुलिस इन घटना के लिए अवैध हथियारों और गोला-बारूद की व्यापक उपलब्धता को ज़िम्मेदार ठहरा रही है, पुलिस के उच्च अधिकारियों के कुछ बेतुके बयान हास्यास्पद एवं शर्मनाक होने के साथ चिन्ताजनक है। उनके हिसाब से जून में ज्यादा वारदात होती हैं, क्योंकि मॉनसून आने के पहले तक किसान खाली बैठे होते हैं। राज्य की राजधानी पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिनदहाड़े 5 शूटर्स ने जिस तरह एक गैंगस्टर की हत्या की, उससे यही लगता है कि कानून-व्यवस्था का डर खत्म हो चुका है। पिछले 10 दिनों में एक के बाद एक कई आपराधिक घटनाओं में व्यापारी गोपाल खेमका, भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार, एक 60 वर्षीय महिला, एक दुकानदार, एक वकील और एक शिक्षक सहित कई हत्याओं ने चुनावी राज्य को हिलाकर रख दिया है।

बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर राजनीतिक घमासान चरम पर है। विपक्ष, खासकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस, जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर लगातार हमलावर है, वही एनडीए इन मुद्दों पर जबावी एवं रक्षात्मक हमला करते हुए चुनाव पर इनके असर को बेअसर करने में जुटी है। लालू यादव के शासनकाल के 'जंगलराज' की भी याद दिलाने की कोशिश एनडीए की पार्टियां कर रही है ताकि विपक्ष इन मामलों पर ज्यादा हावी ना हो। भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बिहार की जनता लालू राज में जो जंगलराज था, उसे भूली नहीं हैं। विपक्ष चाहे जो भी आरोप लगाए बिहार में आज सुशासन का राज है और जो घटनाएं हुई हैं वह योजनागत अपराध के तहत है, जिस पर सरकार कड़ी करवाई कर रही है।' हॉस्पिटल में जिसकी हत्या हुई, वह खुद हत्या के मामले में जेल में बंद था और फिलहाल पैरोल पर बाहर आया था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वारदात में विरोधी गैंग शामिल हो सकता है। इसका मतलब कि राज्य में संगठित अपराध फिर सिर उठा रहा है। इसी महीने, 4 जुलाई को बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या हुई थी और उसमें भी भाड़े के शूटर्स का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी हत्याएं बार-बार हो रही हैं, यह सिलसिला कहीं रुकता नहीं दिख रहा। पक्ष एवं विपक्ष के राजनीतिक दल एवं नेता चाहे जो बयान दें, लेकिन बिहार में अपराध तो बढ़ ही रहे हैं, आमजनता में भय एवं असुरक्षा व्याप्त है।। हाल ही में राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, और गया जैसे प्रमुख शहरों में हुई हत्या और डकैती की घटनाएं न केवल भयावह हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि अपराधी अब पुलिस और प्रशासन से नहीं डरते और पुलिस का अपराधियों पर नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। सड़क पर चल रहे आम लोगों को दिनदहाड़े गोली मार दी जाती है, व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बिहार भले अपराध में कई दूसरे राज्यों से पीछे दिखता हो, लेकिन सच यही है कि आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। राज्य में ये अपराध तब हो रहे हैं, जब पूरा फोकस क्राइम कंट्रोल पर है। बिहार में पिछले तीन वर्षों में अपराध दर में निरंतर वृद्धि हुई है। हत्या, बलात्कार, अपहरण, और लूट जैसे संगीन अपराधों में राज्य शीर्ष स्थानों में शामिल हो गया है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि चुनावी राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही है।

एक समय था जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर उल्लेखनीय सुधार किए थे। लालू-राबड़ी शासन के समय जिसे जंगलराज कहा जाता था, उसके मुकाबले एक उम्मीद जगी थी कि बिहार अब विकास, सुरक्षा और शांति की राह पर है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जनता फिर से असुरक्षा, भय और अराजकता के वातावरण में जीने को मजबूर है। इन स्थितियों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब सरकार के पास प्रशासनिक अनुभव है, गठबंधन के रूप में राजनीतिक ताकत है, तो फिर अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? बिहार में कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे के साथ हमेशा राजनीति का पहलू जुड़ा रहा है। राज्य के लोगों के जहन में कई बुरी यादें हैं और राजनीतिक बाजीगरी में यह कोशिश होती है कि वे यादें कभी कमजोर न पड़ें। अभी तक इसका फायदा सीएम नीतीश कुमार को मिला है। नीतीश और भाजपा ने लालू-राबड़ी यादव के कार्यकाल को हमेशा 'जंगलराज' के तौर पर पेश किया। लेकिन, अब वही सवाल पलट कर उनकी ओर आ रहे हैं, जो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चिन्ता एवं चेतावनी का सबब बनना ही चाहिए।

बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण और गठबंधनों की जोड़तोड़ हमेशा से हावी रही है। लेकिन अब जो नया परिदृश्य बन रहा है, उसमें अपराध और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप भी आम हो गए हैं। हाल ही में कई मामलों में नेताओं और जनप्रतिनिधियों के आपराधिक तत्वों से संबंध उजागर हुए हैं। यह स्थिति न केवल लोकतंत्र के लिए खतरा है, बल्कि जनविश्वास की भी अवहेलना है। यदि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, तो फिर आम जनता के लिए न्याय और सुरक्षा केवल एक सपना बनकर रह जाएगा। हाल के अपराधों की घटनाओं ने विपक्ष को सरकार की नाकामी उजागर करने का मौका दिया है, जबकि भाजपा और जदयू रक्षात्मक रुख अपना रहे हैं और इन घटनाओं को योजनागत घटनाओं का नाम देकर राजद सरकार के समय की आपराधिक घटनाओं के साथ तुलना कर रहे हैं। मगर सूत्रों की माने तो पार्टी इस बात को लेकर तैयारी जरूर कर रही कि, यदि यह मुद्दा संसद के आगामी सत्र में विपक्ष उठाती है तो उस पर कैसे जवाब देना है? जिस बिहार के पूर्ववर्ती सरकारों के कानून एवं व्यवस्था की खराब स्थिति को मुख्य मुद्दा बनाकर एनडीए सरकार सत्ता में आई थी अब यही मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर ठोस कदम चाहिए, न कि केवल वादों की झड़ी। विपक्ष इस समय सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी में है और 'बदहाल कानून-व्यवस्था' को मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहा है।

आरजेडी-कांग्रेस भाजपा और नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि जिनके शासन में कभी सुशासन की मिसाल दी जाती थी, अब वही शासन अपराधियों के आगे बेबस नजर आ रहा है। बिहार के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। सरकार को चाहिए कि वह पुलिस-प्रशासन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दे, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे और राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करे। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ किया जाए ताकि अपराधियों को जल्द सजा मिले। बिहार इस समय एक निर्णायक मोड़ पर है। अन्यथा एक ओर पुराना भयावह जंगलराज लौटने की आशंका है, दूसरी ओर एक सक्षम, उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन की आवश्यकता। यदि वर्तमान सरकार इस संदेश को नहीं समझती, तो आगामी विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिख सकते हैं, जिसमें सुशासन नहीं, जनाक्रोश निर्णायक भूमिका निभाएगा। जनता के लिए भी यह चुनाव एक अवसर है कि वे विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें, न कि जाति या चहेते दल के नाम पर।

संपादकीय | भारत का साफ जवाब, धमकी नहीं चलेगी

इसमें कोई दोराय नहीं कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए सभी जरूरी विकल्पों पर काम होना चाहिए और खासतौर पर इसमें वैसे देशों को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, जो इसमें अपना कुछ प्रभाव रखते हैं। संभव है कि अमेरिका भी रूस-यूक्रेन युद्ध का अंत ही चाहता हो। मगर जिन देशों से इस युद्ध को खत्म कराने के लिए कुछ करने की उम्मीद की जा रही है, क्या धौंस या धमकी के जरिए उनसे ऐसा करा पाना मुमकिन है?

पिछले कुछ समय से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सुविधा के मुताबिक और हित में कई देशों पर शुल्क लगाने या बढ़ाने के विकल्प को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अब रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर भी बेजा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के महासचिव मार्क रूट ने बुधवार को भारत, चीन और ब्राजील को यह चेतावनी दी थी कि अगर वे रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

इससे पहले ट्रंप ने भी यह कहा था कि अगर यूक्रेन को लेकर जल्दी ही शांति समझौता नहीं किया गया, तो रूस से सामान खरीदने वाले देशों पर सौ फीसद तक का शुल्क लगाया जाएगा। जाहिर है, यह बहुध्रुवीय विश्व में अन्य देशों को अपनी सुविधा और नीतियों के मुताबिक फैसले लेने की आजादी और संप्रभुता पर डाला जाने वाला एक दबाव है, जिसकी दिशा अमेरिका की इच्छा के हिसाब से संचालित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारत ने स्वाभाविक ही

प्रतिबंध लगाने की धमकी के खिलाफ सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारत ने गुरुवार को इस मामले में 'दोहरे मापदंडों' के प्रति आगाह किया और जोर देकर कहा कि रूस से उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों और बाजार की गतिशीलता पर आधारित है। दरअसल, दिसंबर, 2022 में जब रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब यूरोपीय संघ और अमेरिका ने यह उम्मीद की थी कि इस पाबंदी से रूस की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा और उसे यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करने पर मजबूर किया जा सकेगा। मगर तब रूस से भारत और चीन ने तेल की खरीद जारी रखी और यही वजह है कि प्रतिबंध ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए।

सवाल है कि अगर नाटो और अमेरिका अन्य देशों के नीतिगत मामलों में इस स्तर पर जाकर दखल देना चाहते हैं, तो क्या यह प्रत्यक्ष रूप से दोहरे मापदंड नहीं हैं! राष्ट्रपति बनने के साथ ही ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म कराने के लिए बढ़-चढ़ कर दावे किए थे। मगर अब यह साफ है कि इस दिशा में ट्रंप की कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टे अमेरिका यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहा है। अब नाटो भारत, चीन और ब्राजील से रूस के राष्ट्रपति को फोन करके शांति वार्ता के लिए गंभीर होने को कह रहा है तो इसके क्या मायने हैं?

भारत के पास अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं, उपलब्धता के सीमित विकल्प हैं और फिलहाल जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसी के मुताबिक कदम उठाना होगा। यों भी एक संप्रभु देश अपनी जरूरतों के मुताबिक ही अपनी दिशा तय करता है और भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है। इसके बावजूद अगर नाटो और अमेरिका की ओर से भारी शुल्क या फिर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी जाती है तो दरअसल यह टकराव और दबाव की वही नीति है, जिसे खत्म करने की वे इच्छा जता रहे हैं।

क्रिप्टो मार्केट ने पहली बार छुआ चार ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा

ट्रंप सरकार की नीतियों से मिली रफ्तार

नईदिल्ली, एजेंसी। क्रिप्टो सेक्टर का बाजार मूल्य शुक्रवार को लगभग चार ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। क्रिप्टोकरेंसी डेटा एग्रीगेटर कोइनगेको के जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। यह आंकड़ा क्रिप्टो सेक्टर के लिए एक मिल का पत्थर है। प्रमुख बाजारों में नियामकीय स्पष्टता, निवेशकों के विश्वास में बढ़ोतरी और संस्थागत निवेश के मजबूत प्रवाह ने इस उद्योग को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है।

अमेरिका ला रहा क्रिप्टो के लिए नियम- अमेरिकी हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव ने गुरुवार को अमेरिकी डॉलर से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी टोकन के लिए एक नियामक ढांचा बनाने के लिए विधेयक पारित किया। इस क्रिप्टोकरेंसी को स्टेबलकॉइन के रूप में जाना जाता है। फिलहाल विधेयक को राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेज दिया गया है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा। हार्ग्रेव्य लैंसडाउन के इक्विटी रिसर्च प्रमुख डेरेन नाथन ने कहा कि ट्रंप की नीति आने के बाद क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर नजरिया पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन इसके बावजूद सांसद अब भी कुछ हद तक सतर्कता बरत रहे हैं।

बिटकॉइन में आई थी 1.8 प्रतिशत की गिरावट

यह क्षेत्र पिछली बार 3.92 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त बाजार मूल्य पर कारोबार कर रहा था, क्योंकि बिटकॉइन, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है, वह 1.8 प्रतिशत गिर गई थी। दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो टोकन, ईथर, पिछली बार 4.5 प्रतिशत बढ़ा था। पिछले तीन महीनों में यह दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गया है।

बिटकॉइन ने इस हफ्ते छुआ रिकॉर्ड स्तर

बिटकॉइन ने इस हफ्ते की शुरुआत में 120,000 डॉलर का आंकड़ा पार कर एक रिकॉर्ड बनाया। ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन का अनुमान है कि 2025 के अंत तक यह 200,000 डॉलर तक पहुंच सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंज के शेयरों में अंतिम बार 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं खुदरा व्यापार मंच, जो क्रिप्टो ट्रेडों का भी समर्थन करता है, उसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

15851 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी धोखाधड़ी का खुलासा, पकड़ी गईं 3558 फर्जी कंपनियां

नईदिल्ली, एजेंसी। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान 15,851 करोड़ रुपये की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 29 फीसदी अधिक है। हालांकि, इस अवधि में फर्जी कंपनियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस तिमाही में केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने कुल 3,558 फर्जी कंपनियों का पता लगाया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह संख्या 3,840 थी। अधिकारियों ने बताया कि हर महीने औसतन 1,200 फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ किया गया। यह गिरावट संकेत देती है कि फर्जी पंजीकरण के खिलाफ चलाया गया अभियान असरदार साबित हो रहा है। इस तिमाही में की गई कार्रवाई के दौरान 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 659 करोड़ रुपये की वसूली भी की गई। वहीं, पिछले साल की समान तिमाही में 26 गिरफ्तारियां हुई थीं और 549 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई थी।

ऐसे हुई करोड़ों की धोखाधड़ी- जीएसटी व्यवस्था के तहत, कंपनियां अपने आपूर्तिकर्ताओं से खरीद पर चुकाए गए टैक्स को आईटीसी के रूप में क्लेम कर सकती हैं। लेकिन फर्जी कंपनियां सिर्फ इस टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने के लिए बनाई जाती हैं, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान होता है।

मखाना टॉप सुपरफूड के रूप में उभरा, बदलती पसंदों से फूड इंडस्ट्री के लिए नए अवसर

नईदिल्ली, एजेंसी। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच भारतीय सुपरफूड मखाना ने उपभोक्ताओं के बीच खास जगह बना ली है। फार्मली की %हेल्दी स्नैकिंग रिपोर्ट 2025% के अनुसार 65 प्रतिशत उपभोक्ता प्रतिभागियों ने मखाने को अपनी पहली पसंद बताया है।

55 प्रतिशत उपभोक्ताओं को प्रिजर्वेटिव-मुक्त विकल्पों की तलाश- रिपोर्ट में हेल्थी स्नैक्स की ओर मजबूत बदलाव की भी चर्चा की गई है। 55 प्रतिशत से ज्यादा उपभोक्ता अब सक्रिय रूप से प्रिजर्वेटिव-मुक्त विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा, आधे से ज्यादा लगभग 52 प्रतिशत ऐसे स्नैक्स को प्राथमिकता देते हैं, जो दोबारा सील होने वाली, पर्यावरण- अनुकूल पैकेजिंग में आते हैं। यह पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।

स्वादयुक्त सूखे मेवे का चलन- सर्वेक्षण के अनुसार उपभोक्ताओं के बीच सुविधा एक प्रमुख कारक बनी हुई है। लगभग 45 प्रतिशत अपभोक्ता बार और सूखे मेवे आधारित मिठाइयों जैसे चलते-फिरते नाशते को पसंद करते हैं। नमकीन विक्लपों में मखाना और स्वादयुक्त सूखे मेवे स्पष्ट रूप से पसंदीदा हैं। इससे बाजार में स्वस्थ नाश्ते के विकल्पों की एक नई लहर चल पड़ी है।

इन रुझानों से यह संकेत मिलता है कि उपभोक्ता अब सेहत पर केंद्रित,

टिकाऊ और सुविधाजनक स्नैक विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यह बदलाव उन ब्रांडों के लिए बड़े अवसर लेकर आ रहा है, जो बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुसार अपने उत्पाद पेश कर रहे हैं।

सुपर-स्नैक में परिवर्तन- रिपोर्ट के अनुसार, मखाना और स्वादयुक्त सूखे मेवे पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरे हैं। 36 प्रतिशत उपभोक्ता उत्तरदाताओं ने भुने हुए और स्वादयुक्त सूखे मेवों को सबसे पसंदीदा नमकीन नाश्ते के रूप में पसंद किया। वहीं 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से मखाना को चुना, जो आधुनिक समय के सुपर-स्नैक में इस परिवर्तन को दर्शाता है।

मखाना बोर्ड का गठन- यह बढ़ती लोकप्रियता भारत सरकार द्वारा बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की हाल की घोषणा के अनुरूप है। निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य राज्य के प्रमुख मखाना उद्योग को बढ़ावा देना है।

चिप्स और वेफर्स की लोकप्रियता बरकरार- हालांकि नए प्रारूप लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन चिप्स और वेफर्स जैसे पारंपरिक विकल्प अभी भी बरकरार हैं। 14 प्रतिशत लोग इन्हें चुनते हैं, इसके बाद 10 प्रतिशत नमकीन और 9 प्रतिशत लोग खाखरा जैसे मल्टीग्रेन स्नैक्स चुनते हैं। मीठे स्नैक्स भी विकसित हो रहे हैं, जबकि चॉकलेट भारत में हमेशा से पसंदीदा रहा है,। मूंगफली का मक्खन, हेजलनट और पिस्ता जैसे मेवे अब स्वाद और स्वास्थ्य के मिश्रण के कारण पसंद किए जा रहे हैं।

ब्रांड लॉयल्टी, जो पहले पारंपरिक बड़ी कंपनियों तक सीमित थी, अब कई प्लेटफॉर्म्स पर फैल रही है। जहां एक ओर ऑफलाइन स्टोर अब भी योजनाबद्ध खरीदारी और खोज का प्रमुख जरिया बने हुए हैं, वहीं क्रिक कॉमर्स और इन्फ्लुएंसर-चालित कंटेंट की बदौलत अचानक स्नैकिंग की आदतों में तेजी आई है।

भारतीय चाय की मांग दुनिया में बढ़ी, एफवाय25 में 26 करोड़ किलोग्राम का हुआ निर्यात

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत के चाय निर्यात में वृद्धि दर्ज हुई है। चार्य बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत से चाय निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2.85 प्रतिशत बढ़ा। देश का चाय निर्यात 250.73 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 257.88 मिलियन किलोग्राम (लगभग 26 करोड़ किलोग्राम) हो गया है।

चाय निर्यात का मूल्य 290.97 रुपये पहुंचा- वहीं प्रति किलोग्राम चाय निर्यात का मूल्य बढ़कर 290.97 रुपये हो गया। यह वित्त वर्ष 2024 के 258.30 रुपये से 12.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

चाय निर्यात में लगातार हो रही वृद्धि- कैलेंडर वर्ष जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान, चाय निर्यात की मात्रा 256.17 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गई। यह जनवरी से दिसंबर 2023 की पिछली अवधि से 10.57 प्रतिशत की वृद्धि है। बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान उत्तर भारत से निर्यात 10.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 155.49 मिलियन किलोग्राम रहा। वहीं दक्षिण भारत से यह 11.02 प्रतिशत के साथ 100.68 मिलियन किलोग्राम रहा।

उत्तर भारत से निर्यात में हुई 8.15 प्रतिशत की वृद्धि

वित्त वर्ष 2025 के दौरान उत्तर भारत से निर्यात की मात्रा 161.20 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गई। यह वित्त वर्ष 2024 के 149.05 मिलियन किलोग्राम से 8.15 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार, दक्षिण भारत से निर्यात 2025 में 4.92 प्रतिशत घटकर 96.68 मिलियन किलोग्राम रह गया। यह इससे पिछले वित्त वर्ष में 101.68 मिलियन किलोग्राम था।

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 40 अरब डॉलर पार्, जानें अश्विनी वैष्णव हैदराबाद में और क्या बोले

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इसमें पिछले 11 वर्षों के दौरान आठ गुना वृद्धि हुई है। वहीं, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में छह गुना वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यह बात कही।

आईआईटी हैदराबाद के 14वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए वैष्णव ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की तीव्र प्रगति पर भी जोर दिया, जिसके अगस्त या सितंबर 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। भविष्य की ओर देखते हुए, वैष्णव ने कहा कि पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, व्यावसायिक स्तर पर, इसी वर्ष बन जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया के शीर्ष पांच सेमीकंडक्टर देशों में से एक बनने की राह पर है, और उन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए आवश्यक पूंजीगत उपकरणों और सामग्रियों पर बढ़ते ध्यान पर भी चर्चा की।

केंद्रीय रेल, सूचना व प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, महज 11 वर्षों में, हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को छह गुना बढ़ा दिया है। यह दोहरे अंकों की छलांग है जिससे कोई भी कॉर्पोरेट ईर्ष्या करेगा। हमने अपने निर्यात को आठ गुना बढ़ाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 40 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात को पार कर लिया है, जो विकास

की एक अभूतपूर्व गति है, जो हमारे जैसे बहुत कम देशों ने देखी है।

उन्होंने इस वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दिया और कहा कि केवल साढ़े तीन वर्षों में, भारत एक संपूर्ण 4ल दूरसंचार स्टैक डिजाइन कर सका। आज, यह लगभग 90,000 दूरसंचार टावरों पर स्थापित है, जो दुनिया के कई देशों के नेटवर्क से भी ज्यादा है।

आईटी मंत्री ने कहा कि दूरसंचार पहल के हिस्से के रूप में, सरकार ने 100 5जी प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जहां छात्र 5जी उपकरणों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामलों पर काम करने और व्यावहारिक समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने भारत की विकास गाथा और अगली पीढ़ी के लिए आधार के पांच उदाहरण दिए- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, एआई, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार क्षेत्र और रेलवे।

उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए केंद्र ने लगभग 270 कॉलेजों और संस्थानों को कैडेंस, सिनोप्सिस और सीमेंस के नवीनतम ईडीए उपकरण दिए हैं और यदि स्टार्टअप को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 340 हो जाती है। वैष्णव ने कहा, दुनिया में कहीं भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इतना बड़ा प्रतिभा विकास कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे के पास इस समय वंदे भारत का तीसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है, जिसका निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है।

75 पार के फार्मूले से कितनों पर लटकेगी उम्र की तलवार ..?

14 विधायक भी आएंगे '75' की चपेट में..!

भोपाल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। हर कोई इसके अलग-अलग मायने निकाल रहा है। मप्र के संदर्भ में बात करें तो 75 साल के फॉर्मूले का इस्तेमाल बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से करती रही है। 2014 के बाद हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कई नेताओं के टिकट उम्र के क्राइटेरिया में काटे गए तो कई नेताओं को इस फॉर्मूले से दूर रखा गया। बीजेपी आने वाले चुनावों में यदि मोहन भागवत के इस फॉर्मूले को सौ फीसदी लागू करती है तो 2028 के विधानसभा चुनाव में 14 विधायकों को सक्रिय राजनीति से रिटायर होने पड़ेगा। हालांकि, एक मीडिया समूह ने जब इन नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा राजनीति खेल का मैदान नहीं है जहां फुटबॉल और कबड्डी खेली जाए। कुछ ने कहा कि अनुभव और वरिष्ठता बाजार में नहीं मिलती। जब एक्सपर्ट से बात की तो वे बोले- राजनीति में उम्र मायने नहीं रखती।

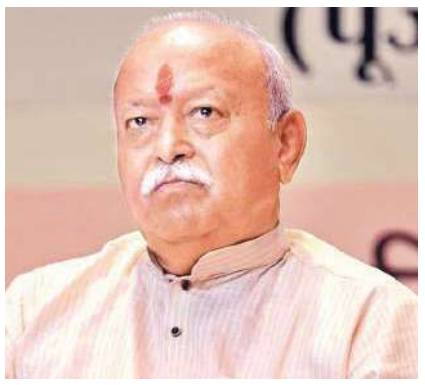

11 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र में नेताओं के रिटायरमेंट का जिक्र किया। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी उम्र कितनी है। पीएम मोदी इसी साल सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे। 11 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। इस बार 11 सितंबर यानी करीब दो महीने बाद पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे।

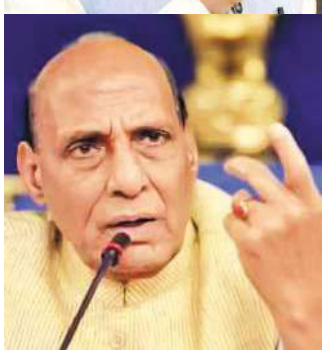

राजनाथ सिंह अभी 74 साल के

केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी जल्द ही 75 वर्ष के हो जाएंगे। अभी राजनाथ सिंह 74 साल के हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1951 है। इसका मतलब है कि उन्हें 75 साल की उम्र पूरी करने में अभी एक साल का समय है।

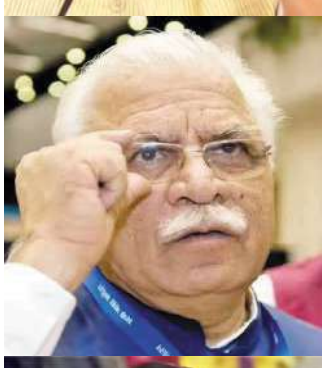

71 साल के हो गए मनोहर लाल खट्टर

बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम भी प्रमुख है। खट्टर की उम्र अभी 71 साल है। उनका बर्थ डेट 5 मई 1954 है। अभी उन्हें 75 वर्ष की उम्र पूरी करने में 4 साल का वक्त है और वे फिलहाल राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय भी हैं।

नितिन गडकरी की उम्र 68

बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी की उम्र पर गौर करें तो अभी वो 68 वर्ष के हैं। उनका जन्म 27 मई 1957 को हुआ। उन्हें 75 वर्ष की उम्र के लिए अभी करीब 7 साल का वक्त है।

शिवराज सिंह हुए 66 साल के

उम्र के मामले बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी 66 साल के ही हैं। उनका जन्म 5 मार्च 1959 को हुआ। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अभी केंद्रीय कृषि मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। उनके 75 साल की उम्र पूरी करने में अभी 9 साल का वक्त है।

60 साल के अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह अभी 75 साल की उम्र के पड़ाव से काफी दूर हैं। अभी शाह की उम्र 60 वर्ष है। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ। इस तरह उन्हें 75 के पड़ाव पर पहुंचने में 15 साल का वक्त है।

मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी नेता की तीखी प्रतिक्रिया

'हम बुजुर्ग हो गए हैं तो क्या कचरे में फेंक देंगे'

भोपाल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल की उम्र में राजनीति से अलग होने के संकेत पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को साथ लेकर चलने से काम बेहतर होता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या माता-पिता को कचरे में डाल दिया जाएगा। कुसमारिया ने यह भी कहा कि अगर वे बुजुर्ग हैं, तो क्या उन्हें भी उठाकर फेंक दिया जाएगा। मध्यप्रदेश में बीजेपी के लगभग 27 विधायक 2028 के विधानसभा चुनाव तक 75 साल के हो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कुसमारिया के सहारे सरकार को घेरा है। उन्होंने ओबीसी आयोग में खाली

पदों और भवन की मांग को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी अगर 75 के फॉर्मूले पर चलती है, तो 27 विधायक किनारे हो जाएंगे। कुसमारिया की बीजेपी में लोधी चेहरे के रूप में पहचान है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है। यह बहस आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से शुरू हुई है। भागवत ने कहा था कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। इस बयान पर मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुसमारिया ने कहा कि बुंदेलखंड में एक कहावत है कि बुजुर्गों को साथ ले गए तो काम अच्छे से हो जाता है। क्या माता-पिता को कचरे में डाल दोगे। हम भी बुजुर्ग हैं, तो क्या हमें भी उठाकर फेंक दोगे। गौरतलब है कि कुसमारिया ने यह बात भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय में कही। वे जिलाध्यक्षों के साथ एक बैठक में शामिल होने आए थे।

'मोदी को किसी की जरूरत नहीं... भाजपा को चाहिए मोदी'

रांची। बीते दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंच से कहा कि नेताओं को 75 साल होने के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। मोहन भागवत के दिए इस बयान के बाद लोगों ने कहा कि उनका इशारा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ था। हालांकि, उन्होंने यह बयान किसी और के लिए दिया था। उनका यह बयान काफी चर्चा में रहा। अब झारखंड की गोड्डा लोकसभा

सीट से सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को जरूरत नहीं किसी चीज की, बल्कि भाजपा को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। इस दौरान निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। आइए जानते हैं उन्होंने पीएम मोदी को लेकर क्या-क्या कहा। मोहन भागवत का बयान और फिर ये चर्चा कि उनका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था, निशिकांत दुबे ने इस चर्चा और आकलनो पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप सहमत हों या असहमत लेकिन हर राजनीतिक दल को एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत होती है, जिसके चेहरे पर पार्टी चलाई जा सके। इस दौरान उनका इशारा सीधे तौर पर पीएम मोदी की तरफ था।

इंडिया-इंग्लैंड टेस्टः

टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन...

● ये स्टार खिलाड़ी भी चोटिल, मैनचेस्टर टेस्ट में खेलना मुश्किल

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है, जिसमें शुभमन ब्रिगेड फिलहाल 1-2 से पीछे है. अब इस टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला 23 जुलाई (बुधवार) से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला जाना है. यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो का हो चुका है. इस मैच में यदि भारतीय टीम हारती है, तो वो सीरीज भी गंवा देगी.

रिपोर्ट के मुताबिक दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकाश दीप ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे हैं. लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में आकाश दीप का प्रदर्शन खास नहीं रहा था और वो सिर्फ एक विकेट ले पाए थे. हालांकि आकाश दीप ने एजबेस्टन टेस्ट मैच में गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था और 10 विकेट झटके थे. अब इंजरी के कारण आकाश दीप की फिटनेस सवालों के घेरे में है और उनका मैनचेस्टर टेस्ट में खेलना तय नहीं है.

तेज गेंदबाजों की इंजरी के बाद भारतीय टीम के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि जसप्रीत बुमराह अगले टेस्ट मैच में खेलें. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने खुलासा किया था कि बुमराह इस दौरे पर केवल तीन टेस्ट मैच खेलेंगे. मौजूदा सीरीज में दो मुकाबले तो बुमराह खेल चुके हैं, ऐसे में वो बाकी के दो में से सिर्फ एक मैच में उतरेंगे. यह देखना बाकी है कि क्या भारतीय टीम बुमराह के लिए अपनी योजनाओं में बदलाव करता है या नहीं. वैस आकाश दीप के इंजर्ड होने के चलते ऐसा लग रहा है कि बुमराह मैनचेस्टर टेस्ट में जरूर खेलेंगे.

पंत-अर्शदीप के अलावा ये खिलाड़ी भी चोटिल

मैनचेस्ट टेस्ट से पहले भारतीय टीम अपने खिलाड़ियों की इंजरी से जूझ रहे हैं. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हाथ में लगी कट के चलते मैनचेस्टर टेस्ट मैच से पहले ही बाहर हो चुके हैं. जबकि उप-कप्तान ऋषभ पंत अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में लगी चोट से रिकवर हो रहे हैं. अब चौथे टेस्ट मैच से सिर्फ तीन दिन पहले भारतीय टीम को एक और झटका लगा है.

अर्शदीप की जगह कौन आया?

इसी बीच अर्शदीप सिंह के चौथे टेस्ट मैच से बाहर होने के बाद दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज को भारतीय टेस्ट स्क्वॉड में जोड़ा गया है. अंशुल घरेलू क्रिकेट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने अब तक के करियर में शानदार प्रदर्शन किया है. हाल ही अंशुल ने भारत-ए की तरफ से इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ दो चार दिवसीय मुकाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने अपनी पेस और सटीकता से मेजबान टीम के बल्लेबाजों को परेशान किया था.

सचिन के साथ अपना नाम ट्रॉफी पर देखता हूं तो बहुत अजीब लगता है: जेम्स एंडरसन

लंदन, एजेंसी। इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने स्वीकार किया कि सचिन तेंदुलकर के साथ ट्रॉफी पर अपना नाम देखकर वह अजीब महसूस करते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में से एक के साथ अपना नाम होना बहुत बड़ा सम्मान है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला की ट्रॉफी का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा है। पहले इसका नाम पटौदी ट्रॉफी था जो भारत के पूर्व कप्तान इफ्तिखार अली खान पटौदी और उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी के नाम पर था। एंडरसन ने कहा, 'यह जरूरी नहीं कि आपके नाम पर ट्रॉफी का होना कितना बड़ा है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि आपके नाम के साथ सचिन तेंदुलकर का नाम है, जो मेरे लिए अब तक के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक हैं।

एथलीट मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल में लंबी कूद का खिताब जीता

7.75 मीटर की लगाई कूद

नई दिल्ली, एजेंसी। श्रीशंकर ने 7.63 मीटर की कूद के साथ शुरुआत की और दूसरे दौर में 7.75 मीटर की कूद लगाई। तीसरी कूद में उन्होंने 7.69 मीटर का फासला नापा। अगला प्रयास फाउल रहा और इसके बाद 6.12 और 7.58 मीटर की कूद लगाई।

भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल के माइया में विश्व एथलेटिक्स उपमहाद्वीपीय टूर के कांस्य स्तर के टूर्नामेंट मीटिंग माइया सिडाडे डो डेसपोर्टो में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। श्रीशंकर ने 7.75 मीटर की कूद लगाई और शीर्ष स्थान हासिल किया। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता श्रीशंकर ने दूसरे दौर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।

श्रीशंकर-तारकोवस्की ने बराबर फासला नापा

श्रीशंकर ने 7.63 मीटर की कूद के साथ शुरुआत की और दूसरे दौर में 7.75 मीटर की कूद लगाई। तीसरी कूद में उन्होंने 7.69 मीटर का फासला नापा। अगला प्रयास फाउल रहा और इसके बाद 6.12 और 7.58 मीटर की कूद लगाई। पोलैंड के पियोत्र तारकोवस्की ने भी 7.75 मीटर की कूद लगाई लेकिन उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास 7.58 मीटर था जो श्रीशंकर के 7. 69 मीटर से कम था।

इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में रचा इतिहास

नई दिल्ली, एजेंसी। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ शनिवार को खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 8 विकेट से जीता। इसी के साथ इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान पर सर्वाधिक महिला वनडे मैच जीतने वाला देश बन गया है।

इंग्लैंड ने अपने घरेलू मैदान पर अब तक 182 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 121 मुकाबले में उसने जीत दर्ज की है। इंग्लैंड से पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के नाम था, जिसने 146 वनडे मुकाबलों में 120 जीते हैं। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम 166 में से 86 मैच जीतकर तीसरे पायदान पर है। भारत ने अपने घर पर 131 में से 81 मैच जीते हैं। भारतीय महिला टीम इस लिस्ट में चौथे पायदान पर है। लॉर्ड्स में खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम महज 6 के स्कोर पर प्रतिका रावल (3) का विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद स्मृति मंधाना ने 51 गेंदों में 42 रन जड़ते हुए टीम को संभाला। उनकी इस पारी में पांच चौके शामिल थे। मंधाना के अलावा दीप्ति शर्मा ने 34 गेंदों में नाबाद 30 रन की पारी खेली, जबकि हरलीन देओल ने 16 और अरुंधति रेड्डी ने 14 रन टीम के खाते में जोड़े। विपक्षी टीम की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने सर्वाधिक तीन शिकार किए। इनके अलावा एम अलॉर्ट और लिंसे स्मिथ को दो-दो सफलता हाथ लगी, जबकि चार्ली डीन ने एक विकेट अपने नाम किया।

बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में भारत ने 29 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 143 रन बनाए। इंग्लैंड को शुरुआत में 29 ओवरों में 144 रन का टारगेट मिला था। मेजबान टीम को एमी जोन्स और टैमी ब्यूमोंट ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 10.2 ओवरों में 54 रन की साझेदारी हुई। टैमी ब्यूमोंट 35 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद एमी जोन्स ने कप्तान नेट साइवर-ब्रंट के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 रन जोड़ते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। 19वें ओवर के दौरान एक बार फिर बारिश ने दस्तक दी और इंग्लैंड के टारगेट में बदलाव हुआ। इंग्लैंड को जीत के लिए 24 ओवरों में 115 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे इंग्लैंड ने 21 ओवरों में हासिल कर लिया। एमी जोन्स 57 गेंदों में 46 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि कप्तान ब्रंट ने टीम के खाते में 21 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से क्रांति गौड़ और स्नेह राणा को एक-एक सफलता हाथ लगी। भारत और इंग्लैंड की टीमें तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं। सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 22 जुलाई को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा।

नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया का द्विवार्षिक सम्मेलन संपन्न

जोगिंदर देव आर्य बने प्रदेश अध्यक्ष, डॉ. किशोर महासचिव और सुनील शर्मा बने कोषाध्यक्ष

हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर पेंशन लागू करे सरकार पत्रकार कल्याण बोर्ड का हो गठन स्वास्थ्य बीमा न होने से मीडिया जगत में रोष

रणजीत टाइम्स : विशेष रिपोर्ट

नई दिल्ली, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया (एनयूजे इंडिया) हिमाचल इकाई का द्विवार्षिक सम्मेलन रविवार को नैना देवी मंदिर परिषद के मातृ आंचल सभागार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा उपस्थित रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी और राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप तिवारी ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य प्रधान डॉ रणेश राणा ने की। प्रदेश महासचिव डॉ. किशोर ठाकुर ने संगठन की दो वर्षों की गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संगठन के 12 जिलों में 200 से अधिक सक्रिय सदस्य हैं और सभी उपमंडलों तथा जिलों में इकाइयों का गठन किया जा चुका है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रणेश राणा ने अपने

कार्यकाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि उन्होंने पिछले दो वर्षों में प्रदेश भर में 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर संगठन को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से उन्होंने पत्रकारों को पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर पेंशन सुविधा, पत्रकार कल्याण बोर्ड के गठन और मध्य प्रदेश की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा देने की मांग की थी, लेकिन न तो पिछली भाजपा सरकार और न ही वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इन मांगों पर कोई कार्रवाई की। राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने कहा कि वर्ष 1972 से संगठन दिल्ली से लेकर संसद तक पत्रकारों की मांगों को लगातार उठाता रहा है, परंतु लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद पत्रकारों की उपेक्षा होती रही है। राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप तिवारी ने कहा कि एनयूजेआई के प्रयासों से देश के आधे राज्यों में सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान निधि (पेंशन योजना) शुरू हो चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश अब भी इससे वंचित है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज और देश के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य करता है, फिर भी उसे सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश सरकारों ने कोई लाभनहीं दिया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर कंवरदीप शर्मा ने पत्रकारिता को एक पवित्र पेशा बताते हुए कहा कि यह माध्यम वंचितों, पीड़ितों और अभावग्रस्त वर्गों की आवाज़ उठाने का कार्य करता है, और इसमें कार्यरत व्यक्ति जीवन भर सीखते रहते हैं। इस अवसर पर दो दर्जन से ज्यादा पत्रकारों को अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने के लिए हिमाचल पत्रकार गौरव अवॉर्ड से नवाजा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी व महासचिव प्रदीप तिवारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और कहा कि पत्रकार से समाज को बहुत अपेक्षाएं रहती हैं और मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े मुद्दे हल भी होते हैं और भ्रष्टाचार का भी खुलासा होता है। उन्होंने हिमाचल पत्रकार गौरव अवॉर्ड से चयनित पत्रकारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और आशा प्रकट की है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर और ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य करेंगे।

ऊना के वरिष्ठ पत्रकार जोगिंदर देव आर्य को चुना प्रदेश अध्यक्ष

कार्यक्रम के अंत में सर्वसम्मति से हुए चुनाव में ऊना के वरिष्ठ पत्रकार जोगिंदर देव आर्य को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त डॉ. किशोर ठाकुर (जिला सोलन) को प्रदेश महामंत्री, गोपाल दत्त शर्मा (जिला सिरमौर) को संगठन मंत्री और सुनील शर्मा (बिलासपुर) को कोषाध्यक्ष चुना गया।

एनयूजे संगठन पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहा सराहनीय कार्य : रणधीर शर्मा

मुख्यातिथि व नैनादेवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि आज पत्रकार कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एनयूजे संगठन इस वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहा है, यह सराहनीय कार्य है। पत्रकारों के मामले व मांगों को मैं विधानसभा में उठाऊंगा और भाजपा की सरकार आने पर लागू करवाने का पूरा प्रयास करूंगा।

दैनिक रणजीत टाइम्स

जिला एवं तहसील स्तर पर

एजेंसी देना है

अपना बायोडाटा सम्पूर्ण विवरण के साथ हमें प्रेषित करें।

सम्पर्क करें

8224951278 :: 9827068888

जन्मदिन की अग्रिम शुभ सूचना

"रंजीत टाइम्स" में अब आप अपने या अपने प्रियजनों का जन्मदिन एक दिन पहले ही निशुल्क प्रकाशित करवा सकते हैं!

बस हमें भेजिए: 1 जन्मदिन मनाने वाले की फोटो

2 उसका पूरा नाम- 3 बधाई देने वाले का नाम जन्मदिन के एक दिन पहले ही विज्ञापन भेज दें, ताकि समय रहते प्रकाशित किया जा सके।

भेजने का नंबर (Aditya): 8224951278

रंजीत टाइम्स में आपका विज्ञापन पूरी तरह मुफ्त प्रकाशित किया जाएगा!
अपने जज़बातों को शब्द दें – सिर्फ रंजीत टाइम्स के साथ।
टीम रंजीत टाइम्स- "आपका अपना अख़बार, आपकी आवाज़"

रणजीत टाइम्स